35° अधिकतम | 27° न्यूनतम | सूर्योदयः 05.04 सूर्यास्तः 18:44

दिल्ली-चेन्नई की तरह पटना में भी होगा बस टर्मिनल

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राजधानी में बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बस टर्मिनल। रोजाना तीन हजार बसों के आवागमन की क्षमता वाला यह बस टर्मिनल दिल्ली और चेन्नई के इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) जैसा होगा।

यहां हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। गुरुवार को 1, अणे मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से पटना-गया हाईवे पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बस टर्मिनल बनाने पर सहमति बन गई। नगर विकास सचिव डॉ.एस.सिद्धार्थ ने बताया कि पटना-गया हाईवे पर 26 एकड़ जमीन पर आईएसबीटी के समान बस टर्मिनल बनाया जाएगा। यहां बसों के अलावा निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी की पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें रेस्टोरेन्ट, फूड कोर्ट, कमिंशयल व मल्टी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होगा। यहीं पटना शहर के लिए शुरू की जाने वाली सिटी सेवा की बसों की भी पार्किंग होगी। बैठक में यह भी तय हुआ कि पटना सहित सभी 11 नगर निगमों में सिटी बस सर्विस की योजना बनाई जाएगी। इसका क्रियान्वयन एक स्पेशल पर्पस व्हेकिल के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव योजना विकास विजय प्रकाश, पथ निर्माण सचिव प्रत्यय अमृत और वन पर्यावरण सचिव दीपक कुमार सिंह समेत कई अधिकारी शामिल हुए।

2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे अत्याधुनिक सुविधाओं वाले टर्मिनल बनाने में

26 एकड़ जमीन पर (पटना-गया हाइवे) बनाया जाएगा आईएसबीटी

3000 बसों का रोजाना आवागमन की होगी क्षमता

11 नगर निगमों में सिटी बस सर्विस की योजना भी बनाई जाएगी

रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का टेंडर शीघ्र

गंगा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। लगभग 245 करोड़ रुपये की योजना को नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की मंजूरी मिल चुकी है। नगर विकास सचिव ने बताया कि कलेक्ट्रेट घाट से नौजर घाट तक 6.5 किलोमीटर लम्बाई में मौजूद सभी घाटों के सौन्दर्यीकरण की डिजाइन तैयार कर ली गई है। सभी घाटों को 20 फुट चौड़े पाथ-वे से जोड़ा जाएगा। गंगा बेसिन के लिए यह परियोजना मॉडल होगी।

ठोस कचरा प्रबंधन

पटना नगर निगम सहित सभी नगर निगम और नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया को तेज की जाएगी। नए सिरे से मार्ग निर्देश जारी किए जाएंगे। नगर निकायों के लिए वाहनों व उपकरणों की खरीद इसी नीति के माध्यम से की जाएगी।

एक अणे मार्ग में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह व अन्य।